(मार्च 1993 का मूल्य स्तर) वाली नाथपा झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (6 x 250 मे.वा. - 1500 मे. वा.) नाथपा झाकड़ी नाथवा झाकड़ी पावर कारपोरेशन (एनजेपीसी) के निर्माणाधीन है। अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार बांध की ऊंचाई 60.5 मीटर है। उत्तरोतर भूस्खलन के कारण जलाशय की भण्डारण क्षमता सीमान्त रूप से घटी है। परियोजना के अनुमोदन के समय यथा परिकल्पित व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान लाभो समेत क्षतमा के अधिकतम समुपयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए एनजेपीसी ने बांध की ऊंचाई 7.0 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अब, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के जांचाधीन है। 4337.95 करोड़ रुपये (मार्च 1993 का मूल्यास्तर) की अनुमोदित लागत अनुमानो की तुलना में के.वि.प्रा. द्वारा मूल्यांकित की गई संशोधित समापन लागत 7217.05 करोड़ रुपये है।

टिहरी बांध का कार्य पूरा होना

822. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सन् 1962 में प्रारंभ हुई टिहरी बांध परियोजना एक सफेद हाथी सिद्ध हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के अनुमान बदलते रहते हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि जब से यह परियोजना केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से लेकर टी.एच.डी.सी. को सौंपी है तब से इसकी गुणवत्ता का ह्रास और धन की बर्बादी हुई है,

(घ) क्या यह भी सच है कि टी.एच.डी.सी. के पास उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के समान अनुभवी लोगों की भारी कमी है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार स्थिति में सुधार लाने और अंतिम रूप से निर्धारित समय सीमा में इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना को मूलत: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के तौर पर निष्पादित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना की लागत 1370.86 करोड़ रु० (1987 मे मूल्य स्तर पर) थी। वर्ष 1989 में इसके राज्य सरकार से टिहरी जल विद्युत विकास निगम को अंतरित किए जाने के पश्चात् 1000 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता के साथ जल विद्युत परियोजना चरण-2 और टिहरी बांध का अनुमोदन 2815 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर किया गया था। इस परियोजना की अतंतिम अनुमानित लागत दिसम्बर, 1997 के मूल्य स्तर पर 4570 करोड़ रुपये है। लागत में वृद्धि, सामान्य मूल्य बढ़ोत्तरी, पुनर्वास पैकेज पर व्यय और पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों के कारण से है। इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित की गई है क्योंकि उत्पादित ऊर्जा की लागत का परिकल्पन पुनर्वास पैकेज और पर्यावरणात्मक सुरक्षा उपायों पर किए गए अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखते हुए 1.20 रुपये प्रति यूनिट किया गया है।

(ग) कार्य की गुणवत्ता अथवा निधियों के अपव्यय के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। कार्य की प्रगति इस परियोजना पर अब तक किए गए व्यय के अनुरूप रही है। काफर बांध की ऊंचाई बढ़ाकर पृथ्वी स्तर 661 कर दी गई है। भूमिगत विद्युत गृह के सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और खुदाई का 60% कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य बांध का कार्य आरंभ हो चुका है और बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। उत्पादन संयंत्र और उपस्कर के लिए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस प्रकार परियोजना संबंधी सभी प्रमुख गतिविधियों चल रही हैं।

टिहरी जल विद्युत विकास निगम के पास अनुभवी इंजीनियरों से सुसज्जित एक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग है। इसके अतिरिक्त निर्माण की गुणवत्ता जल विद्युत क्षेत्र स्वतंत्र विशेषज्ञों से सुसज्जित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा नियमित अंतरालों पर जांच और आवधिक निरीक्षण पर निर्भर करती है। परियोजना स्थल पर तैनात रूकी विशेषज्ञ भी निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। टिहरी जल विद्युत विकास निगम के पास उ.प्र. सिंचाई विभाग तथा अन्य विभागों से अनुभवी इंजीनियर नियमित सूची पर हैं। इस परियोजना को वर्ष 2002 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

Power Projects in Nepal

823. **DR. JAGANNATH MISHRA:** Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether India and Nepal have signed any agreement in power sector in February, 1996;

(b) if so, the main features of the agreement;

(c) to what extent Government have agreed to help Nepal in the power sector;

(d) whether Indian private parties have agreed to set up power projects in Nepal; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) A "Treaty" concerning the integrated development of the Mahakali river was signed in February 1996. Govt. of India has agreed to supply 300 cusecs of water from Tanakpur in the dry season and 70 MU of power free of cost. Both countries have agreed to implement the Pancheshwar multi-purpose project as an integrated project. The Detailed Project Report for the Pancheshwar multi-purpose project would be prepared after discussions between experts of the two countries. A number of meetings of the Joint Group of Experts of the Pancheshwar project has been held. The joint group of Experts have identified the important issues which require to be resolved in order to finalise the Detailed Project Report.

(b) to (e) The Government of Nepal are exploring the possibilities of development of hydro electric power through private participation.

Reforms in Power Sector

824. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what reforms in the power sector are being contemplated by his Ministry including in areas of transmission, conservation of energy, liquid fuel projects and standardisation of fuel supply agreements, as reported in 'The Hindustan Times' dated 18th May, 1998;

(b) whether his Ministry has given three months time to the State Governments to set up the State Electricity Regulation Commission if they want to avail of subsidy on interest loans from National Power Finance Corporation, Rural Electrical Corporation etc., and if so, the details thereof; and

(c) the amount of power subsidy likely to be made in the 1998-99 budgetary allocations?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) The reforms contemplated in the power sector relate to establishment of Electricity Regulatory Commissions both at Central and at States level for rationalisation of tariffs and matters related thereto; to recognise transmission as independent activity of generation and distribution; encouraging energy conservation and establishment of Bureau of Energy Efficiency; and standardization of liquid fuel supply agreement to be entered into by the IPPs with the Oil Public Sector Undertakings.

(b) As on date Government has not approved any such proposal.

(c) The Government of India do not provide subsidy for tariff of power in its budgetary allocation as the same is provided by the respective State Governments in their budget.

Demand and Supply of Electricity

825. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is a huge gap between the demand and supply of electricity in the country;

(b) if so, what is its present status of demand and supply of electricity;

(c) since when this gap persists; and

(d) by when this gap is likely to be bridged?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALM): (a) and (b) The power supply position in the Country during 1997-98 and April, 1998 is given below:

(Figures in MU net)

	1997-98	April, 98
Requirement	424505	37581
Availability	390330	34707
Shortage	34175	2874
%Shortage	8.1	7.6

(c) and (d) Inspite of significant growth in power generation over the years the shortage remains and is mainly on account of growth in load demand for power, outstripping the growth in generation.

As per the preliminary exercise undertaken by the Government, the capacity addition of 40.226 MW is assessed to be fessible during the Ninth Plan period (1997-98—2001-02). If this capacity materialises, the all India energy deficit is likely to be 1.4% by the end of Ninth Five Year Plan.